



## विचार बिन्दु

जहाँ चक्रवर्ती सप्त्राट की तलवार कुंठित हो जाती है, वहाँ महापुरुष का एक मधुर वचन ही काम कर देता है। -हरिओंथ

## उमर खालिद की जमानत याचिका निरस्त होने के निहितार्थ

दि

ल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नवीन चावला और शैलेन्द्र कौर की खंडपीट ने उमर खालिद और आठ अन्य लोगों के विरुद्ध यू.ए पी.ए और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत चल रहे प्रकार में जमानत याचिका 2 सितम्बर 25 को खारिज कर दी। यह छठी बार था जब उमर खालिद की याचिका खारिज की गई। यहाँ यह लिखना प्रासंगिक होगा कि बताकर के अरोप में दोषी और सजा याप्ता आसाराम और बाबा राम रहीम अनेक पार पेरोल पर जेल से बाहर आ चुकी है।

आइए, देखते हैं, उमर खालिद और आठ अन्य लोगों पर सावत्व में क्या आरोप है? इनके विरुद्ध फरवरी, 2020 में दिल्ली में हुए दोनों की सजिस रखने का आरोप है। इन दोनों में 53 लोग मारे गए थे। इन पर यू.ए पी.ए पी.ए लगाया गया है। जमानत याचिका खारिज करने वाले 30 प्रूफ़ों के निर्णय में न्यायालय ने विस्तार से बतला दिया है कि अधियुक्तों ने आतंकियों की गतिविधियों के लिए उत्तरोन्नयों के लिए बड़वयं बताया। किसी भी विद्यार्थी या अधिकारी को अंतर्गत करना का प्रयास किया। यह उत्तरोन्नयों है कि उमर खालिद और आठ अन्य लोग गत 5 वर्षों से जेल में बंद हैं। इनके विरुद्ध अभी तक न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ भी नहीं हो पाई है। अब तक छह बार इनके जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।

मानीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनेक बार यह कह चुके हैं कि न्यायिक प्रकारणों में जारी रखा जाए है और जमानत याचिका खारिज कर के यह स्पष्ट संदेश दें दिया गया है कि यह सिद्धांत सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू नहीं होता है। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और चुनाव विशेषक योगेंश यादव ने 'इंडियन एक्सप्रेस' में दिनांक 5 सितम्बर 2025 को प्रकाशित अपने लेख में यह साफ़ बताया है कि 'मुंबई में जनवरी, 2020 में आयोगित एक बड़े सम्मेलन में जो बांतें उमर खालिद ने नारिकात संसाधन कानून के विरोध में कही थीं, उस सम्मेलन में वही भी जोड़ी थीं। उन्होंने भी लगानी बढ़ी थीं। अतः, उन्होंनी भी जेल में होना चाहिए था। उन्होंने एक बार भी छूटात तक के लिए नहीं बुलाया गया। इस सम्मेलन में लगाव एक लाख व्यक्ति उपस्थित थे। अतः एक सदैस तो यह गया है कि देश के सभी नागरिकों के लिए कानून समान रूप से लागू नहीं होता। यदि आप बहुत संघर्षक वर्ष से हैं तो कानून एक तरह से लागू होगा।'

इसी प्रकार यदि आप सरकार समर्थक वर्ग के हैं तो आप के साथ लागू किया जाएगा। यह भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत है, जिसके प्रतावना में कहा गया है कि देश के सभी नागरिकों को राजनीतिक, अधिकारी और सामाजिक न्याय बिना जाति, धर्म, लिंग, भाषा के भेदभाव के सुनिश्चित करना जाएगा। उमर खालिद से संबंधित यह निर्णय संविधान की मूल भावना पर गहरी चोट करता है। यह प्रकार उसे प्रकार में कुछात होगा जिस प्रकार एकीएम जबलपुर वाला मामला, जिसका निर्णय आपातकाल में दिया गया था और जिसे आज भी नागरिक अधिकारों के हनन के फैसले के रूप में यदि किया जाता है।

अधियुक्त के बकीलों ने जब न्यायालय का ज्ञान इस ओर आकर्षित किया कि 5 वर्ष तक बिना दावत के उके पक्षकार जेल में बंद हैं और इस कारण उका भविष्य बदल जाता है कि सरकार जब नारिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में जारी करने के लिए उत्तर दिखाई देगी। माना जाता है कि सरकार जब नारिकों के बारे में जारी करने के लिए उत्तर दिखाई देगी। यह भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत है, जिसके प्रतावना में नारिकों को राजनीतिक, अधिकारी और सामाजिक न्याय बिना जाति, धर्म, लिंग, भाषा के भेदभाव के सुनिश्चित करना जाएगा। उमर खालिद से संबंधित यह निर्णय संविधान की मूल भावना पर गहरी चोट करता है।

इस निर्णय से दूसरा संदेश यह जाता है कि यदि आप सरकार की विचारधारा के समर्थक हैं तो आपको कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा और आपके नागरिक अधिकारों की रक्षा भी होगी, किंतु यदि आप सरकार के किसी भी निर्णय के विरुद्ध खड़े हो तो फिर केवल सरकार बल्कि न्यायपालिका भी आपके अधिकारों के बारे में जारी करने के लिए उत्तर दिखाई देगी। माना जाता है कि सरकार जब नारिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में जारी करने के लिए उत्तर दिखाई देगी। यह भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत है, जिसके प्रतावना में नारिकों को राजनीतिक, अधिकारी और सामाजिक न्याय बिना जाति, धर्म, लिंग, भाषा के भेदभाव के सुनिश्चित करना जाएगा। उमर खालिद से संबंधित यह निर्णय संविधान की मूल भावना पर गहरी चोट करता है। यह प्रकार उसे प्रकार में कुछात होगा जिस प्रकार एकीएम जबलपुर वाला मामला, जिसका निर्णय आपातकाल में दिया गया था और जिसे आज भी नागरिक अधिकारों के हनन के फैसले के रूप में यदि किया जाता है।

अधियुक्त के बकीलों ने जब न्यायालय का ज्ञान इस ओर आकर्षित किया कि 5 वर्ष तक बिना दावत के उके पक्षकार जेल में बंद हैं और इस कारण उका भविष्य बदल जाता है कि सरकार जब नारिकों के बारे में जारी करने के लिए उत्तर दिखाई देगी। माना जाता है कि सरकार जब नारिकों के बारे में जारी करने के लिए उत्तर दिखाई देगी। यह भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत है, जिसके प्रतावना में नारिकों को राजनीतिक, अधिकारी और सामाजिक न्याय बिना जाति, धर्म, लिंग, भाषा के भेदभाव के सुनिश्चित करना जाएगा। उमर खालिद से संबंधित यह निर्णय संविधान की मूल भावना पर गहरी चोट करता है।

इस निर्णय से दूसरा संदेश यह जाता है कि यदि आप सरकार की विचारधारा के समर्थक हैं तो आपको कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा और आपके नागरिक अधिकारों की रक्षा भी होगी, किंतु यदि आप सरकार के किसी भी निर्णय के विरुद्ध खड़े हो तो फिर केवल सरकार बल्कि न्यायपालिका भी आपके अधिकारों के बारे में जारी करने के लिए उत्तर दिखाई देगी। माना जाता है कि सरकार जब नारिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में जारी करने के लिए उत्तर दिखाई देगी। यह भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत है, जिसके प्रतावना में नारिकों को राजनीतिक, अधिकारी और सामाजिक न्याय बिना जाति, धर्म, लिंग, भाषा के भेदभाव के सुनिश्चित करना जाएगा। उमर खालिद से संबंधित यह निर्णय संविधान की मूल भावना पर गहरी चोट करता है।

संबूच न्यायालय ने अपने निर्णयों में कही बार कहा है कि केवल अपने विचार को अधिव्यक्त करना, इटर्साप्स पर संदेश भेजना, कविता लिखना, नारा लगाना या सरकार के किसी कानून के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए उत्तर दिखाई देगी। माना जाता है कि उमर खालिद से संबूच नारिकों के बारे में जारी करने के लिए उत्तर दिखाई देगी। यह भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत है, जिसके प्रतावना में नारिकों को राजनीतिक, अधिकारी और सामाजिक न्याय बिना जाति, धर्म, लिंग, भाषा के भेदभाव के सुनिश्चित करना जाएगा। उमर खालिद से संबंधित यह निर्णय संविधान की मूल भावना पर गहरी चोट करता है।

जब न्यायपालिका भी अपने आपको स्वतंत्र अनुभव नहीं करती एवं दबाव में काम करती

दिखाई देगी तो फिर लोकतंत्र की जड़ें कमज़ोर होने की आशंका उत्पन्न होती है।

यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत को एक कमज़ोर लोकतंत्र के रूप में

देखा जाने लगा है। अधिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैमाने पर भारत दुनिया के नीचे

पायदान वाले देशों में सम्मिलित हो गया है।

देने और गोली मारने के लिए उके संदेश भेजना, कविता लिखना, नारा लगाना या सरकार के किसी कानून के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए उत्तर दिखाई देगी। यह भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत है, जिसके प्रतावना में नारिकों को राजनीतिक, अधिकारी और सामाजिक न्याय बिना जाति, धर्म, लिंग, भाषा के भेदभाव के सुनिश्चित करना जाएगा। उमर खालिद से संबंधित यह निर्णय संविधान की मूल भावना पर गहरी चोट करता है।

इस निर्णय से दूसरा संदेश यह जाता है कि यदि आपको कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा और आपके नागरिक अधिकारों की रक्षा भी होगी, किंतु यदि आपको कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा और आपके नागरिक अधिकारों की रक्षा भी होगी। यह भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत है, जिसके प्रतावना में नारिकों को राजनीतिक, अधिकारी और सामाजिक न्याय बिना जाति, धर्म, लिंग, भाषा के भेदभाव के सुनिश्चित करना जाएगा। उमर खालिद से संबंधित यह निर्णय संविधान की मूल भावना पर गहरी चोट करता है।

यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत को एक कमज़ोर लोकतंत्र के रूप में देखा जाने लगा है। अधिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैमाने पर भारत दुनिया के नीचे

पायदान के देशों में सम्मिलित हो गया है।

अधिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे प्रमुख मौलिक अधिकार है जो लोकतंत्र का प्रमुख संभव भी है। इसी अधिव्यक्ति पर भारतीय संविधान का विरुद्ध एक अंदर आर्द्ध जड़ करने के लिए उत्तर दिखाई देगी। माना जाता है कि अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत को एक कमज़ोर लोकतंत्र के रूप में देखा जाने लगा है। अधिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैमाने पर भारत दु











यह कार्यक्रम आदर्श नहीं है। यह ऐसा ही है और इसमें कोई बदलाव ही होने वाला है, इसलिए हमें इससे निपटने के तरीके ढूँढ़ने होंगे... हमें ऐसे तरीके ढूँढ़ने होंगे जिससे हम इस बार को तुलना में अधिक तेजी से काम शुरू कर सकें। - डेंबन मैं कुलम

इंग्लैंड टीम के मुख्य कोच, टीम को अपने व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम से बेहतर तरीके से निपटना होगा।



### आज का खिलाड़ी ▶



